

न्यायालय राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष: एम०के०सिंह
सदस्य

पूर्णविलोकन प्रकरण क्रमांक 2535-11-2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 6-7-2016
पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 2622-दो-2014
निगरानी ।

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री उधम सिंह रघुवंशी
निवासीगण ग्राम मलावनी तहसील मुगावली
जिला अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदिका

विरुद्ध

म०प्र० शासन

.....अनावेदक

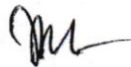
(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)

(अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी.एन. त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 23-11-2016 को पारित)

यह पूर्णविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्र 2622/दो/2014
निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता सन्
1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अतर्गत प्रस्तुत किया गया है।





2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक को ग्राम मलावनी स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 302 हैक्टर में से रकवा 1.500 का व्यवस्थापन तहसीलदार मुगावली के प्रकरण क 161/अ-19/89-90 आदेश दिनांक 05.10.1990 से स्व० श्री पन्नालाल जी के नाम से उक्त भूमि का व्यवस्थापन किया गया स्व. पन्नालाल जी का कोई वारिस न होने के कारण आवेदक को दिनांक 23.4.2012 को स्व. पन्नालाल जी ने उक्त भूमि का वसियत आवेदक के हित में कर दिया जिस कारण उक्त निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई । उक्त व्यवस्थापन किये जाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं रही किन्तु अपर कलेक्टर अशोकनगर ने स्वयमेव निगरानी में लेकर प्रकरण क 524/97-98 में पारित आदेश दिनांक 30.3.99 से उक्त व्यवस्थापन आदेश को वगैर सुनवाई का मौका दिये व्यवस्थापन आदेश को काफी लम्बे समय के बाद स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त कर दिया जिस अपर कलेक्टर के स्वयमेव निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी 446/2009-2010 प्रस्तुत की गई जो आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2010 से निरस्त की गई जिस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2622/दो/2014 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 6.7.2016 से निरस्त कर दी गई । इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है ।

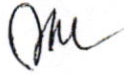
3/ आवेदक द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से निरस्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है तहसीलदार द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार जांच करने के उपरांत किसी की कोई आपत्ति न आने पर व्यवस्थापन किया गया है जो व्यवस्थापन वर्ष 1990 में किया गया है अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय बाद वगैर आवेदक को सुने व सुनवाई का मौका दिये व्यवस्थापन को लगभग 8 वर्ष बाद स्व.निगरानी में लेते हुये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो आलोच्य आदेश कंतई उचित एवं न्याय संगत नहीं है ।



माननीय वरिष्ठ उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने कई न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं कि स्वनिगरानी में प्रकरण को सिर्फ 180 दिन के भीतर लेना चाहिए काफी लम्बे समय के बाद प्रकरण को स्व. निगरानी में नहीं लेना चाहिए । उक्त अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय 8 वर्ष के अंतराल के बाद प्रकरण को स्व. निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो कतई उचित एवं न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है एवं पुर्नविलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों एवं इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को उक्त भूमि का व्यवस्थापन तहसील मुगांवली न्यायालय के प्रकरण क्र 161अ-19/89-90 में पारित आदेश दिनांक 05.10.1990 से किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी समय के बाद स्व. निगरानी में लेते हुये प्रकरण क्र 524/97-98 स्व निगरानी में दर्ज करते हुये अपने आदेश दिनांक 30.3.99 से आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया गया है जवकि अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्व० निगरानी में काफी समय के अंतराल के बाद लिया है निश्चित समय के अन्दर में नहीं लिया है दूसरे पक्ष को सुने वगैर , उसको सूचना पत्र जारी किये वगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नहीं है। आवेदकगण द्वारा उक्त पटटे पर प्राप्त भूमि पर आज काफी धन खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है उसमें ट्यूबवेल पम्प लगाए उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर काफी मेहनत करके भूमि को उपजाऊ कृषि योग्य बनाया गया है इसलिये अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वनिगरानी में लेते हुये पटटे निरस्त

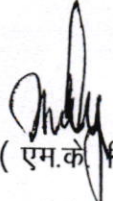




करने से आवेदक को काफी मानसिक व शारीरिक व आर्थिक हानि हुई है। इस सम्बन्ध में 2000 आर०एन० 161 मान.उच्च न्यायालय , 2000आर०एन० 67 उच्च न्यायालय ,2010 (4) एमपीएलजे 178,1996 आर०एन० 137, ,1969 एससी 1297 ,1990 आर.एन. 77, 1992 आर. एन. 163 के न्याय दृष्टांतों में अभिमत दिया गया है । कि स्व० निगरानी में कोई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिए काफी अंतराल के बाद नहीं एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं करना चाहिए कलेक्टर अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्व निगरानी में लिया गया है व कतई उचित एवं नियमानुकूल नहीं है। इस वैधानिक तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । एवं आवेदक को उक्त निगरानी पेश करने में हुये विलम्ब को सदभावना पर मानते हुये न्याय हित में क्षमा किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-07-2016 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क 622/2009-10 पारित आदेश दिनांक 28-08-2010 एवं अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा स्व० निगरानी 524/97-98 में पारित आदेश दिनांक 30-3-1999 विधिवत एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं। तथा तहसीलदार मुंगावली का आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन प्रकरण क 161/अ-19/89-90 में पारित आदेश दिनांक 05-10-1990 स्थिर रखा जाता है ।

E. M.


(एम.के. सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर